



P. Abhimanyu
General Secretary

BSNL EMPLOYEES UNION

Central Head Quarters

Ph.: 011-25705385
Fax : 011-25894862

Main Recognised Representative Union,
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar,
Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110008
E-mail : bsnleuchq@gmail.com, Website : www.bsnleu.in

बीएसएनएलईयू/ 102 (सर्कुलर सं. 05)

14 अप्रैल 2020

सेवा में,

सर्किल सचिव,
केंद्रीय पदाधिकारी,
और जिला सचिव।

सामाजिक दूरी बनाए रखकर 21.05.2020 को दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन आयोजित करें।

साथियो,

बीएसएनएलईयू के अखिल भारतीय केंद्र ने बीएसएनएल कार्यालयों के सामने, 21.05.2020 को पूरे देश में 'दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन' आयोजित करने का निर्णय लिया है। चूंकि, यह लॉक-डाउन अवधि है, सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए प्रदर्शनों का आयोजन किया जाना चाहिए। जिन मुद्दों के लिए यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं: -

1. काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर प्रति दिन 12 घंटे करने के खिलाफ।

देश में लागू किए गए लॉक-डाउन का उपयोग करते हुए, काम के घंटों को प्रतिदिन 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे प्रति दिन किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के निर्णय का गंभीर उल्लंघन है। 1919 में आयोजित इस सम्मेलन में, आईएलओ ने एक दिन में 8 घंटे काम करने और एक सप्ताह में 48 घंटे काम करने का निर्णय लिया था। भारत सरकार ने 1921 में आईएलओ के इस निर्णय की पुष्टि की है और तब से इसका पालन किया जा रहा है।

लेकिन, 2014 में सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार श्रम कानूनों को कॉर्पोरेट्स के पक्ष में बदलने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। यह गंभीरता से फ़ैक्ट्रीज एक्ट, 1948 को बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि काम के घंटे बढ़ाए जा सकें। देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आम हड़तालों की एक श्रृंखला आयोजित करके इसका विरोध किया है।

अब, देश में जारी लॉक-डाउन अवधि का उपयोग करते हुए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की राज्य सरकारों ने चुपचाप काम के घंटों को 8 घंटे प्रति दिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के मौन समर्थन से किया जा रहा है। 8 घंटे का कार्य दिवस अपना रक्त बहाकर और अपार बलिदान देकर हासिल किया गया है। इसलिए, भारत के मजदूर वर्ग को काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने के प्रतिगामी निर्णय के खिलाफ लड़ना होगा

2. अप्रैल, 2020 वेतन का तत्काल भुगतान।

अप्रैल, 2020 के महीने के वेतन का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। महासचिव ने निदेशक (वित्त) और निदेशक (मानव संसाधन) के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। लेकिन, कोई यह बताने की स्थिति में नहीं था कि वेतन कब दिया जाएगा। बीएसएनएल प्रबंधन ने एक सोच बना ली है, जिसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना उनकी अंतिम प्राथमिकता बन गई है। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन हर महीने समय पर दिया जाए।

3. ठेका श्रमिकों के मुद्दे।

संविदा कर्मियों को पिछले दस माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। कई संविदा कर्मी इसके कारण पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। इसके अलावा, कॉरपोरेट कार्यालय ने, संविदा कर्मचारियों की छंटनी के लिए, साथ ही साथ उनके काम के घंटों को कम करने के लिए 30-09-2019 को पत्र जारी किया है। बीएसएनएलईयू ने बीएसएनएल कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेडरेशन (बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ) के साथ मिलकर कई आंदोलन किए हैं। इस मुद्दे को कई सांसदों द्वारा संसद में भी उठाया गया था। लेकिन, ये सब बहरे कानों पर पड़ा है। अब, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि, अनुबंधित श्रमिकों को लॉक-डाउन की अवधि के दौरान उनके वेतन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, बीएसएनएल प्रबंधन इन निर्देशों को लागू नहीं कर रहा है। इसके अलावा, बीएसएनएल प्रबंधन उन सभी कार्यों को भी आउटसोर्स कर रहा है जो अब तक संविदा कर्मियों द्वारा किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन और सामाजिक सुरक्षा उपायों से इनकार करने के अलावा, फिर से बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है।

4. आउटडोर ट्रीटमेंट सीलिंग को 23 से घटाकर 15 दिन का वेतन।

08.05.2020 को जारी किए गए पत्र के माध्यम से, बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की जा रही चिकित्सा सुविधा में भारी कटौती की है। तदनुसार, आउटडोर उपचार के लिए सीलिंग को 23 दिनों के वेतन से घटाकर 15 दिन का वेतन पर कर दिया गया है। यह गहरी चिंता का विषय है कि, प्रबंधन ने मौजूदा चिकित्सा सुविधा में कटौती के लिए यह निर्णय लिया है जब बीएसएनएल के कर्मचारियों को राष्ट्र के लोगों के साथ मिलकर कोरोना वायरस रोग के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कंपनी के शीर्ष अधिकारी कंपनी के खर्च पर विलासिता का लाभ उठाते हैं, यह अत्यधिक निंदनीय है कि खर्च में कटौती की आड़ में आम कर्मचारियों की मौजूदा चिकित्सा सुविधा में कटौती की जा रही है। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को पहले चाहिए कि सामान्य कर्मचारियों की सुविधाओं पर अंकुश लगाने से पहले, खुद के लिए अल्पव्ययता उपायों को लागू करें।

प्रदर्शन की मांगें।

उपर्युक्त शर्तों के मद्देनजर, बीएसएनएलईयू के अखिल भारतीय केंद्र ने निम्नलिखित मांगों पर 21.05.2020 को प्रदर्शनों का आह्वान करने का निर्णय लिया है: —

- 1) आईएलओ के फैसले का सम्मान करें। काम के घंटे प्रति दिन 8 से बढ़ाकर 12 घंटे न करें।

- 2) अप्रैल, 2020 के लिए तुरंत वेतन वितरण। हर महीने वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
 - 3) संविदा कर्मियों के वेतन बकाया का तुरंत भुगतान करें। कार्यों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेका श्रमिकों की छटनी न करें।
 - 4) आउटडोर ट्रीटमेंट सीलिंग को 23 दिनों से कम करके 15 दिनों का भुगतान करने के फैसले को वापस लिया जाए।
5. सामाजिक दूरी बनाए रखें – प्रदर्शन पट्टिका (प्लेकार्ड) – मीडिया कवरेज की व्यवस्था करें। देश में जारी तालाबंदी की स्थिति के मद्देनजर, अखिल भारतीय केंद्र ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शन का आयोजन करते समय सामाजिक दूरी को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए। मांगों को हाइलाइट करने के लिए प्रदर्शन में भाग लेने वाले कामरेडों को प्लेकार्ड प्रदर्शित करना चाहिए। कार्यक्रम के लिए पर्याप्त मीडिया कवरेज की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

अखिल भारतीय केंद्र द्वारा सभी सर्किल और जिला सचिवों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रदर्शन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी प्रयास करें।

प्लेकार्डों के लिए मैटर को इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

सधन्यवाद,

आपका



(पी अभिमन्यु)
महासचिव